products from six countries, the details of which are given below:

1978	1979	1980
Iraq	Iraq	Iraq
Pakistan	Pakistan	Pakistan
Iran	Iran	Iran
Kuwait	Kuwait	Kuwait
USSR	USSR	USSR
Sri Lanka	Sri Lanka	Sri Lanka

(b) Imports of crude oil and petroleum products during the years 1978, 1979 and 1980 (upto June) are given below:

(Quantity in million tonnes)

Year	Crude Oil	Petroleum Products
1978 . .	14.58	3.14
1979 . .	16.58	3.23
1980 (upto June)	7.83	1.71

(c) The Government intends to meet the import requirements of crude in the future also by supplies from our traditional sources as also from new potential sources that are being explored at present. Attempts are also being made to intensify our exploration activities and plans are being made for the exploitation of our established reserves with a view to increase the indigenous production of crude oil.

(d) Crude Oil contracts are generally concluded with Government owned companies of the Oil Producing and Exporting Countries. Imports of Petroleum Products are also effected either by negotiating with government owned companies of Oil Producing and Exporting Countries or by floating tenders. In view of this need for offering any special incentive in the matter does not arise.

Oil Exploration in Gujarat

7740. SHRI MOHAN LAL PATEL: Wil the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there are more possibilities of oil exploration in some parts of Gujarat;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government for its exploration;

(c) how many surveys have been conducted and reports presented of such oil exploration during the last three years and during 1st February to 15th July, 1980 and surveys which are likely to be conducted during 1980, 1981 and 1982; and

(d) the results and outcome of the said surveys and how and when it will come into effect?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) Yes, Sir.

(b) There are more possibilities of oil exploration in the Cambay Basin and the Shoal area of the Gulf of Cambay. ONGC propose to detect and explore stratigraphic and subtle traps by using more sophisticated techniques.

(c) A total of 18 party years of seismic work has been carried out in Gujarat during the last 3 years, *viz.*, 1977-78, 1978-79 and 1979-80, and 41 reports submitted. During the period 1st February, 1980 to 15th July, 1980, 6 seismic parties operated in Gujarat, and submitted 4 reports. Over the next 3 years *viz.*, 1980-81, 1981-82 and 1982-83, 27 party years of seismic surveys is proposed to be carried out. In addition, it is also proposed to carry out shallow marine seismic surveys in some areas.

(d) the data collected in 1979-80 is under processing. The results of surveys made earlier are being continuously made use of in the exploration programme. It is a continuing process.

based on feed back of the earlier data as well as new technology, and as such it cannot be said whether any final report would be available by any specific date.

केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण उपायों पर प्रति वर्ष खर्च की जाने वाली धनराशि

7741. **श्री दया राम शाक्य:** क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाढ़ नियंत्रण उपायों पर प्रति वर्ष 300 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो इससे संबंधित स्कीम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलवाया गया है कि कठाहार नहर योजना पर 2,000 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो उस पर विशेष रूप से इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई कि प्रति वर्ष केवल बाढ़ नियंत्रण उपायों पर ही 300 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी, जबकि कठाहार नहर योजना के निष्पादन से बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई में भी सहायता मिलेगी और इस पर खर्च की जाने वाली धनराशि के एक बड़े भाग की पूर्ति भी विश्व-बैंक द्वारा की जायेगी?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) (क) इस बात की संभावना है कि छठी योजना की अवधि (1980—85) में वार्षिक परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और वह चालू वर्ष अर्थात 1980-81 के 168.59 करोड़ रुपये से बढ़कर 1984-85 तक 300 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो जाएगी।

(ख) प्रश्न का संबंध संभवत: श्री दस्तुर द्वारा तैयार की गई गारलैंड नहर स्कीम से है । इस स्कीम की लागत, श्री दस्तूर द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार, 2000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 24,095 करोड़ रुपए है। वस्तुत: इसकी लागत इससे कहीं अधिक बैठेगी । इस स्कीम पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि इसे तकनीकी की दृष्टि से दोषपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से बहुत महंगा समझा गया था। इसके अलावा, इस स्कीम से, जिस रूप में यह तैयार की गई है, बाढ़ नियंत्रण संबंधी कोई लाभ-प्राप्त नहीं होगा।

पांचों पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक योजना में सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई भूमि

7742. **श्री मूलचन्द डागा :**
श्री गिरिधर गोमांगे:

क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कार्यान्वित की गई पांचों पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक में सिंचाई के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और प्रत्येक योजना में कितनी भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई और प्रत्येक योजना पर कितना व्यय किया गया ;

(ख) क्या पांचों योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अब तक व्यय की गई राशि पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हो रहा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे): (क) विवरण संलग्न है (विवरण-एक)।

(ख) वित्तीय लक्ष्य साधारणतया प्राप्त कर लिए गए थे और यहां तक कि ये लक्ष्य कुछ मामलों में बढ़ भी गए थे । वास्तविक लक्ष्यों की पांचवी योजना (1974 - 78) में लगभग प्राप्त कर लिया था। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारणों को संलग्न विवरण - दो में दिखाया गया है ।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं से राजस्व एकत्रित किया जाता है और लेखाओं को भी रखा जाता है ; इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।